MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Conrtitution of India."

The motion was adopted.

श्री श्रीचन्द गोयल : मैं विधेयक को पेश करता हूं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : We come to Bills to be taken up for general discussion. Shri K. R. Ganesh, absent. Shri Narayana Reddy, absent. Shri Yamuna Prasad Mandal, absont. Shri Madhu Limaye.

18.23 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(*Omission of Article 314*)

by Shri Madhu Limaye

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान की धारा 314 को संविधान से हटाने वाले मेरे विधेयक पर यह सदन विचार करे।.........

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

"That the Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration".

You may continue next time. Now, the Home Minister.

18.24 hrs.

STATEMENT RE-PROROGATION OF BOTH HOUSES OF JAMMU AND KASHMIR STATE LEGISLATURE

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : Mr. Deputy Speaker, Sir, Government have received reports that the Governor of Jammu and Kashmir has prorogued both the Houses of the Jammu and Kashmir Legislature with effect from 8-00 A. M. tomorrow, the 14th March, 1970. It has been stated in a press note reported to have been issued by the Jammu and Kashmir Government that the order of prorogation has been necessitated on account of the agitation launched in Jammu by various groups and parties which has seriously affected the proceedings of the current session of the Legislature.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN (Chamba) : On a point of order ,Sir. You Cannot ask a Question on a statement made by a Minister. Nor can you ask a clarification.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU (Chittoor) : You are 10 years behind.

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने काश्मीर सरकार के द्वारा जो प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित की गई, है उस का सारांश ही सदन को बताया है, जिसमें एक बहुत गम्भीर बात उन्होंने बताई है कि चूंकि जो आन्दोलन वहां चल रहा है, उस आन्दोलन की वजह से विधान सभा का कार्य नहीं चल पा सकता है, इस लिये विधान सभा का सत्रावसान किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, जब कोई भी सरकार यह वक्तव्य दे कि किसी आन्दोलन के कारण विधान सभा का काम नहीं चल सकता है, तो उसका साफ मतलब है कि कानून और संविधान उस राज्य में खतम हो चुका है। ऐसी स्थिति में संविधान की दफा 356 के तहत राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति का मतलब है केन्द्र सरकार को अधिकार है कि वहां का शासन अपने हाथ में ले । इस में कहा गया है —

"If the President, on receipt of a report from the Governor of a State or otherwise"....

अदरवाइज पर ध्यान दीजिये, यदि गवर्नर रिपोर्ट न दे और आपकी अपनी जानकारी हो तो भी

* Published in Gazette of India Extra-ordinary Part II, Section 2, dated 13-3-70.

[श्री मधु लिमये]

आपको कार्यवाही करने का अधीकार है।

"is satisfied that a situation has arisen in which the government of the State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution, the President may by Proclamation assume to himself all or any of the functions of the government of the State"....

और घोषणा करे—

"declare that the powers of the legislature of the State shall be exercisable by or under the authority of Parliament".

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मुद्दा यह है – क्या गृह मंत्री जी इस बात की सफाई देंगे – आज तक प्रोरोगेशन के बहुत सारे कारण हमने यहां पर देखे हैं, लेकिन यह तो बड़ा अद्भुत कारण देखने में आया है कि आन्दोलन की वजह से विधान सभा का कार्य नहीं चल सकता। इस से स्पष्ट है कि संविधान और कानून वहां बिलकुल टूट चुका है। मेहरबानी करके काश्मीर राज्य को आज ही रात के 12 बजे से पहले अपने हाथ में ले लीजिये।

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour) : I do not want to go into details. I would have expected from the Home Minister not a repetition of a press statement issued by the Kashmir Government but categorical statement of what has happened there and the basis of the action taken.

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि होम मिनिस्टर साहब ने पूरे तथ्य सदन के सामने नहीं रखे, क्योंकि सादिक साहब ने अपने स्टेटमेन्ट में यह कहा है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को पूरी रिपोर्ट दे दी है। अच्छा यह होता कि सारी चीजें सामने आतीं और जैसा मधु लिमये जी ने कहा जनसंघ का आन्दोलन वहां डेढ़ महीने से चल रहा है। इधर तो रोज आंदोलन चलते हैं तो क्या यहां रोज हाउस को प्रोरोग करते जायेंगे? यहां क्या मजाक है? गवर्नर ने जिस चीफ मिनिस्टर की वहां मैजोरिटी नहीं है, उसको को चीफ मिनिस्टर बनाये रखने में टूल का काम किया है। मैं इतनी बात कह कर अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा कि आप सादिक साहब से कहिये कि वे इस्तीफा दें।

श्री शशि भूषण (खारगोन) : उपाध्यक्ष महोदय, काश्मीर एक बार्डर स्टेट है, वहां पर एक गम्भीर समस्या पैदा कर दी गई है। वहां पर कोई आन्दोलन किसी संस्था ने चलाया हुआ है, जिससे वहां राज्य को खतरा उत्पन्न हो गया है और वह संस्था कैसी है – एक तो वे हैं जो पाकिस्तान से कुछ सहयोग लेकर चलते हैं या कोई धार्मिक संगठन है। तो मैं चाहता हूं कि उस संस्था को फौरन बैन किया जावे ताकि वहां का प्रशासन ठीक प्रकार से चलाया जा सके।

SHRI RAJASEKHARAN (Kamekapura) : The Home Minister has just repeated what has appeared on the teleprinter and what has been heard over AIR. Unfortunately, the situation in Kashmir is so serious that we cannot remain silent spectators. Therefore, I would request him to give a direction to the Governor so that he immediately calls the State legislature into session so that the issue can be settled on the floor of the House.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : उपाध्यक्ष जी, आज दोपहर में जब हम भोजन के बाद वहां पर एकत्रित हुए थे तब मैंने यह सुझाव दिया था कि काश्मीर की आन्तरिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि वहां सिवाय राष्ट्रपति शासन के और कोई दूसरा समाधान नहीं है। स्थिति यह है कि 72 सदस्यों की विधान सभा में सत्तारूढ़ पार्टी के 62 सदस्य थे, उन में से 35 अलग हो गये, लिहाजा 45 एक ओर हो गये और 27 सरकार के पक्ष में रह गये। वहां की सरकार अपना बहुमत खो चुकी है।

इस के अलावा राज्यपाल महोदय ने जो किया है—यानी असेम्बली का सत्रावसान किया है, उस का बहुत बड़ा कारण यह बताया है कि राज्य में तनावपूर्ण स्थिति हो गई है। इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ लगता है, जरूर है। ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार के लिये सिवाय राष्ट्रपति शासन के कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इस अवसर का लाभ उठाना चाहिये और काश्मीर में राष्ट्रपति शासन अविलम्ब लागू करना चाहिये।

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई दक्षिण): मैं यह जानना चाहता हूं क्या यह सही है कि सादिक साहब ने अपना त्याग पत्र दिया है? अगर दिया है तो क्यों उसको छिपाकर रखते हैं? उसको तत्काल स्वीकार करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाये।

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़): मैं इस बात की आशा रखता था कि हमारे गृह मंत्री जी सचमुच जम्मू कश्मीर से कोई जानकारी प्राप्त करके इस सदन को अवगत करायेंगे परन्तु उन्होंने तो न केवल सादिक साहब के त्याग-पत्र को छिपाकर रखा है बल्कि प्रधान मंत्री के पास क्या रिपोर्ट आई है उसको भी छुपाकर रखा है। कम से कम इस बात की आशा हम उनसे नहीं रखते थे कि इस समय वे इस सदन को एक प्रकार से अंधेरे में रखेगें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक—कोई सदन इस बात का निर्णय न करे कि सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित होता है तब तक क्या राज्यपाल को इस बात का अधिकार है कि वह विधान सभा का सत्रावसान कर दे?

SHRI CHENGALRAYA NAIDU (Chittoor): Conditions in Kashmir are not bad except that the Chief Minister has lost the majority. In Bengal there is so much trouble, but there thay have not done anything like this. There is no civil or any other trouble in Kashmir except that the Chief Minister has lost his majority. The Home Minister comes forward with the press note when he has got so much resources at his command and he could have got the information by phone or wireless. The only thing is that the Prime Minister or the Home Minister will fly to Kashmir and try to get back all the the Members to the side of Mr. Sadiq. They are taking this stand only for that.

श्री अब्दुल गनी डार (गुड़गांव): डिप्टी-स्पीकर महोदय, बात कुछ भी नहीं है और ह तो सब कुछ है। कुछ नहीं इसलिए कि कांग्रेस के पास मेजारिटी है, वे चाहे सादिक साहब को रखें चाहे हटाये। या फिर श्री डी० पी० धर को चीफ मिनिस्टर बना दे ताकि एक ही मुसलमान चीफ मिनिस्टर जो कि इस देश में है उसका भी किस्सा खत्म हो जाये।

[شری عبدالغنی ڈار (گڑگاؤں) - ڈپٹی سپیکر مہودے - بات کچھہ بھی نہیں ہے اور ہے تو سب کچھہ ہے - کچھہ نہیں اس لیئے کہ کانگریس کے پاس میجاریٹی ہے - وہ چاہے صادق صاحب کو رکھے چاہے ھٹائے - یا پھر شری ڈی پی دھر کو چیف منسٹر بنادے تا کہ ایک ھی مسلمان چیف منسٹر جو کہ اس دیش میں اس کا بھی قصہ ختم ھو جائے -]

श्री झारखंडे राय (घोसी): उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री महोदय ने जो बयान दिया है वह कतई तसल्ली बख्श नहीं है। जम्मू काश्मीर एक सीमान्त प्रदेश होने के नाते मुझे ख्याल था कि गृह मंत्री जी इस विषय में सदन को विश्वास में लेंगे। मैं समझता हूं पूरे वाकयात का बयान यहां पर दिया जाये उसके बाद ही यह सदन अपनी राय दे सकता है कि वहां पर प्रेसीडेन्ट रूल लागू किया जाये या न किया जाये।

SHRI INDER J. MALHOTRA (Jammu) : I would only want to submit one thing to the Home Minister. You have seen and I am sure that the Home Minister personally is also convinced that the reasons given for the prorogation of the Assembly are not genuine. There are other reasons which made the Governor take this action. Keeping in view the political situation in the State and the dangers which are ahead if the political situation deteriorates, I request the hon. Home Minister to take immediate steps for the restoration of democracy in the State and the normal functioning of democracy.

श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी (श्रीनगर) : मैं ने सुबह भी अर्ज किया था और खास तौर पर चव्हाण साहब से अर्ज करूंगा, इस सदन की आगाही के लिए कि कांग्रेस पार्टी के वहां पर दो हिस्से हो गए हैं – एक सादिक साहब का और दूसरा मीर कासिम साहब का। सादिक साहब के साथ अगर आज मेजारिटी नहीं है तो वह कासिम के साथ होगी। यह इनके घर का मामला है। हमें न कासिम से ताल्लुक है और न सादिक से ताल्लुक है--एक इंडेपेन्डेन्ट मेंम्बर के हैसियत से लेकिन मैं यह चाहूंगा कि वहां इस किस्म की तबाही न हो क्योंकि दूसरी कोई जमात वहां कश्मीर में नहीं है जो कि इस निजाम को चला सके। मैं होम मिनिस्टर से कहूंगा कि स्टेटमेंन्ट देना और प्रेस रिपोर्टस को पढ़ना, वह सही है लेकिन यह चीज सामने रखते हुए कि आप एक सिचुएशन से डील करते हैं, आप किसी को लाड दे दें – हमें उससे भी कोई गर्ज नहीं है–लेकिन लाड देते देते कश्मीर को तबाह न करें। इससे बढ़कर गैरजिम्मेदाराना स्टेटमेंन्ट हो नहीं सकता है कि साहब आन्दोलन चल रहा है। आन्दोलन दो महीने से चल रहा था लेकिन असेम्बली बुलाई गई, असेम्बली ने 15 दिन काम किया। सब कुछ हुआ लेकिन उससे कुछ फर्क भी हुआ? और जो आन्दोलन है वजह यही है कि लोग कहते हैं कि कश्मीर में 12 किलो राशन मिलता है श्रीनगर के लोगों को तो जम्मू में भी 12 किलो दे दिया जाये। इस के पीछे और कोई चीज नहीं है। न कोई पाकिस्तानी हमला है और न ही चीन का खतरा है। कुछ भी नहीं है। आज अगर चीफ मिनिस्टर एलान करे कि हां, मैं कन्सीड करता हूं हालांकि गजेन्द्रगडकर कमीशन की सिफारिश भी है कि ऐसा मिलना चाहिए, तो फिर वह आन्दोलन खत्म हो जायेगा। इस लिए आन्दोलन का बहाना लेकर असेम्बली को प्रोरोग करना, मैं समझता हूं इस से हम दुनियां में जलील होते हैं। खास तौर पर काश्मीर के सिलसिले में जब इस तरह की बात हो जाये तो दुनिया हमारी तरफ देखती है। एक ही मसला है कश्मीर का जिसमें हम इन्टरनेशनली इन्वाल्ड हैं। पाकिस्तान के साथ कश्मीर, चाइना के साथ कश्मीर और सेक्योरिटी कोंसिल में कश्मीर। हालांकि सेक्योरिटी कोंसिल में कश्मीर के मामले में मैं उसका कायल नहीं हूं और मैं कहता हूं

Once for all, the Kashmir question had been decided and settled irrevocably; a decision had been taken;

लेकिन यह चीजें जो सामने आ जाती हैं तो क्यों? जिसके साथ आज बहुमत है वह आपका ही है।

As far as I know Qasim owes loyalty to Indiraji and Jagjivan Ram and they have said so in their statement.

लेकिन आप हम पर कांस्टीट्यूशन पर जुल्म क्यों कर रहे हैं। आप प्रोरोग करने के आदि हो गये है।

It was started by my friend Dr. Karan Singh; it is again repeated.

AN HON. MEMBER : It was done for Bakshi.

श्री गुलाम मोहम्मद बख्शी : But I think Bakshi was arrested during the night; I hope Qasim will not be arrested in the night and Trilochan Dutt also.

मैं यही अर्ज करूंगा, एक दोस्त के नाते, एक साथी के नाते आप इन चीजों में न पड़िए, फैक्शनलिज्म में न पड़िए, क्यों कि उससे कश्मीर में तबाही होगी । आप इसमें फौरन दखल दीजिये ।

[شری غلام محمد بخشی (شرینگر) میں نے صبح بھی عرض کیا تھا اور خاص طور پر چوہان صاحب سے عرض کرونگا - اِس سدن کی آگاھی کے لئے کہ کانگریس پارٹی کے وھان پر دو حصہ ھوگئے ھین - ایک صادق صاحب کا اور دوسرا میر قاسم صاحب کا - صادق صاحب کے ساتھ اگر آج میجارٹی نہین ھے تو وہ قاسم کے ساتھ ھوگی - یہ اُنکے گھر کا معاملہ ھے - ھمین نہ قاسم سے تعلق ھے اور نہ صادق سے تعلق ھے - ایک انڈیپینڈینٹ ممبر کی حیثیت سے - لیکن مین یہ چاھونگا کہ وھان اس قسم کی تباھی نہ ہو کیونکہ دوسری کوئی جماعت وھان کشمیر مین نہین ھے جو کہ اس نظام کو چلا سکے - مین ھوم منسٹر سے کہونگا کہ اسٹیٹمینٹ دینا اور پریس رپورٹس کو پڑھنا - یہ صحیح ھے لیکن یہ چیز سامنے رکھتے ھوئے کہ آپ ایک سچویشن سے ڈیل کرتے ھین - آپ کسی کو لاڈ دے دین - ھمین اُس سے بھی کوئی غرض نہیں ھے - لیکن لاڈ دیتے دیتے کشمیر کو تباہ نہ کریں - اس سے بڑھکر غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمینٹ ھو نہین سکتا ھے کہ صاحب آندولن چل رہا ھے - آندولن دو مہینہ سے چل رہا تھا لیکن اسمبلی بلائی گئی - اسمبلی نے ١٥ دن کام کیا - سب کچھہ ھوا لیکن اُس سے کچھہ فرق بھی ھوا - اور جو آندولن ھے وہ یہی کہ لوگ کہتے ھین کہ کشمیر میں ١٢ کیلو راشن ملتا ھے شرینگر کے لوگون کو تو جمو میں بھی ١٢ کیلو دے دیا جائے - اِسکے پیچھے اور کوئی چیز نہیں ھے - نہ کوئی پاکستانی حملہ ھے اور نہ ھی چین کا خطرہ ھے - کچھہ بھی نہیں ھے - آج اگر چیف منسٹر اعلان کریں کہ ھاں - میں کنسیڈ کرتا ھون - حالانکہ گجیندر گڈکر کمیشن کی سفارش بھی ھے کہ ایسا ملنا چاھیئے - تو پھر وہ آندولن ختم ھوجائیگا - اسلئے آندولن کا بہانا لیکر اسمبلی کو پروروگ کرنا - مین سمجھتا ھون اس سے ھم دنیا میں ذلیل ھوتے ھین - خاص طور پر کشمیر کے سلسلہ مین جب اس طرح کی بات ھو جائے تو دنیا ھماری طرف دیکھتی ھے - ایک ھی مسئلہ ھے کشمیر کا جسمین ھم انٹرنیشنلی انوالوڈ ھین - پاکستان کے ساتھہ کشمیر - چین کے ساتھہ کشمیر اور سیکیورٹی کونسل مین کشمیر - حالانکہ سیکیورٹی کونسل میں کشمیر کے معاملے مین میں اُسکا قائل نہین ھوں اور مین کہتا ھون لیکن یہ چیزین جو

Once for all, the Kashmir question had been decided and settled irrevocably; a decision had been taken.

سامنے آ جا تی ھین تو کہون - جس کے ساتھہ آج بہومت ھے وہ آپکا ھی ھے -

As far as I know Qasim owes loyalty to Indiraji and Jagjivan Ram and they have said so in their stat4ment.

لیکن آپ ھم پر اور کانسٹی ٹیوشن پر ظلم کیون کر رھے ھین - آپ پروروگ کرنے کے آدی ھو گئے ھین -

It was started by my friend !Dr. Karan Singh; it is again repeated.

AN HON. MEMBER : It was done for Bakshi.

SHRI GULAM MOHAMMAD BAKSHI :

But I think Bakshi was arrested during the night. I hope Qasim will not be arrested in the night and Triloehan Dutt also.

مین بھی عرض کرونگا ایک دوست کے ناتے - ایک ساتھی کے ناتے کہ آپ اِن چیزون مین نہ پڑیے - فیکشنلزم مین نہ پڑیے کیونکہ اس سے کشمیر مین تباھی ھوگی - آپ اس مین فوراً دخل دیجئے -]

SHRI Y. B. CHAVAN: I can very well understand the concern of the hon. Member of the fact that when the House was sitting it was prorogued. It it very difficult for me to express a view on the merits of the matter. As I have said, I would have liked to wait sometime before making a statement. Now, naturally I could make a statement on the facts available to me and for that I can only depend upon the Press note issued by the Kashmir Government......(*Interruptions*)

SHRI KANWAR LAL GUPTA: The Prime Minister had talked to the Chief Minister.

SHRI JYOTIRMOY BASU: Has not the Governor made a full report ?

SHRI Y. B. CHAVAN: In these matters the Governor acts as head of the State; he does not report to the Central Government.

SHRI JYOTIRMOY BASU: I find it difficult to accept.

SHRI Y. B. CHAVAN: You do not accept it even when we say good things (*Interruptions*). My point is this. I am not really justifying the Chief Minister's advice to the Governor. Whether he should have given that advice or should not have given that advice is a different matter. I am not expressing any views. But the fact is that the Governor was given that advice and the Governor has accepted it and the Government had explained why it was necessary.... (*Interruptions*.) ....I wish the House will be called again. As I see the situation, the House will have to be called this month because the budget has to be passed.

I would like to say one more thing. One hon. Member mentioned about it is a fact that the Chief Minister did telephone to the Prime Minister to inform her that the House is prorogued. He has not given any more information.

18.41 hrs.

BOMBAY ATOMIC AUTHORITY BILL*

SHRI GEORGE FERNANDES *rose*—

MR. DEPUTY-SPEAKER: Is it for the introduction of the Bill ?

As a special case, I am allowing it.

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई-दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बम्बई में अथवा उस के निकट एक आणविक संयन्त्र स्थापित करने के प्रयोजन से एक प्राधिकरण के गठन और तत्संबंधी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाय।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the formation of an Authority for the purpose of setting up an atomic plant in or near Bombay and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मैं विधेयक को पेश करता हूं।

18.42 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

APPOINTMENT OF PARLIAMENTARY COMMISSION TO EXAMINE ELECTION EXPENCES

SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN (Chamba): Sir, the experience of the past 20 years has shown that the election law in India needs reconsideration and it also needs reconsideration to the extent of the limit which we have provided for the election expenses. The initial charge was that if we do not put at limit on the election expenses, then probably the weaker sections of society will not be able to fight the election. But experience has shown that whether there is a limit or not, the election expenses would be the same.

I would give a few examples to show that in fact the system of providing a limit

* Published in Gazette of India Extraordinary, Part II. section 2, dated 13-3-70.